Unit 3
Planning in India
[भारत की आर्थिक योजना]

- **आर्थिक नियोजन (Economic Planning)**

➢ **Meaning:-**

आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसे आर्थिक संगठन से है जिसमें सभी भिन्न-भिन्न लोगों , उद्योगों और औद्योगिक संस्थानों को एक समन्वित इकाई के रूप में संचालित किया जाता है जिसके द्वारा निर्धारित अवधि में जनता की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का नियंत्रित उपयोग होता है।

➢ **Objectives(उद्देश्य):-**

नियोजन के उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक होते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. **पूर्ण रोजगार:-**

आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना तथा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य होता है।

2. **संतुलित विकास:-**

आर्थिक नियोजन का उद्देश्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है । संपूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में समानता लाने के लिए देश के अविकसित भागो का विकास करना अत्यंत आवश्यक है , ताकि सामाजिक समानता तथा संतुलन बना रहे।

3. **असमानताओं को दूर करना:-**

अर्थव्यवस्था में विकास के साथ-साथ धन एवं आय का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकरण होता जाता है , जिससे जिसे दूर करना योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य होता है । प्रगतिशील कर नीति के द्वारा धनी वर्ग से जो करों के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उसे निर्धन वर्ग पर व्यय कर दिया जाता है । इसके अलावा सरकार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, राशनिंग व्यवस्था तथा मूल्य नियंत्रण जैसी नीतियों से भी आय की असमानता को कम करने का प्रयास करती है।

4. **अवसर की समानता (Equality in Opportunities):-**

राष्ट्र की समस्त कार्यशील जनसंख्या को काम करने , विकास करने तथा जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करना।

5. **अधिकतम उत्पादन(Maximum Production):-**

उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण व वैज्ञानिक ढंग से पुनर्वितरण करना तथा तकनीकी ज्ञान कुशल श्रम तथा योग्य साहसीयों का उचित तरीके से उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

6. **आत्मनिर्भरता:-**

अल्पविकसित देशों की योजनाओं में एक मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होता है। इसलिए वे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपनाकर कुछ दशकों में औद्योगिक एवं कृषि विकास द्वारा आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं।

7. **आर्थिक स्थिरता (Economic Stability):-**

अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं , जिनका मुख्य कारण कम या अधिक उत्पादन होता है। जिसके कारण कीमतें बढ़ने और कम होने लगती हैं, इसलिए आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता कायम करना होता है।

8. **साधनों का उचित प्रयोग:-**

योजना में लक्ष्यों को पूर्व निर्धारित करके उनके अनुसार साधनों का उचित प्रयोग किया जाता है। जैसे- खनिज, वन, जल, विद्युत तथा मानवीय साधन आदि।

9. **गरीबी दूर करना:-**

विकासशील अर्थव्यवस्था में गरीबी के दुष्चक्र बेरोजगारी तथा असमानताओं का संबंध होता है । इसलिए योजनाओं के उद्देश्यों में गरीबी दूर करना भी पाया जाता है।

10. <u>आधुनिकीकरण:-</u>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हमेशा ही देश के विकास के लिए जरूरी समझा गया है । आधुनिकीकरण प्रक्रिया से उत्पादन का ढांचा बदलेगा , उत्पादक क्रियाओं में विविधता आएगी , टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और संस्थागत परिवर्तन होंगे और इन सबसे अर्थव्यवस्था आधुनिक एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी ।

11. <u>अधिकतम सामाजिक कल्याण:-</u>

सरकार ऐसे नियम लागू करती है , जिससे प्रत्येक साधनों को समान अवसर प्राप्त हो । ऐसा करने से साधनों का उचित उपयोग होता है और सामाजिक कल्याण में वृद्धि भी होती है ।

12. <u>सामाजिक सुरक्षा:-</u>

सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत चिकित्सा , बीमा, बेरोजगारी, आवास, मनोरंजन, उचित मजदूरी आदि सम्मिलित होते हैं, इससे कार्यकुशलता के साथ-साथ समाज कल्याण में भी वृद्धि होती है ।

• <u>रणनीति (Strategy of the Economic Planning):-</u>

1. व्यक्तिगत हित के विपरीत सामाजिक हित ।
2. प्राथमिकताओं के निर्धारण का सिद्धांत ।
3. अधिकतम कल्याण ।
4. राष्ट्रीय क्षमता का विवेकपूर्ण उपयोग ।
5. समुचित विकास नीति का सिद्धांत ।
6. राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना ।
7. आर्थिक नियंत्रण का सिद्धांत ।
8. संवैधानिक दृष्टिकोण ।
9. राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति तथा परंपराओं को जीवित रखना ।
10. घरेलू तथा विदेशी उद्यमियों को खोजना तथा उन्हें सहायता देना ।

• <u>आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां एवं असफलताएं(Board achievements and failure):-</u>

भारत में आर्थिक नियोजन को 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ किया गया है । 1951 से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है । 12वीं पंचवर्षीय योजना को आखिरी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है , क्योंकि अब नीति आयोग आ चुका है ।

• <u>उपलब्धियां (Achievements):-</u>

1. Increase in per capita income and national income (प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि) ।
2. Development of Agriculture (कृषि का विकास) ।
3. Industrial development (औद्योगिक विकास) ।
4. Increase in Savings and Investments (बचत व विनियोग दरों में वृद्धि) ।
5. Development of foreign trade (विदेशी व्यापार का विकास) ।
6. Modernization (आधुनिकीकरण)
7. Expansion of education (शिक्षा का प्रसार) ।
8. Progress in banking sector (बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति) ।
9. Progress in mean of transport and communication (परिवहन एवं संचार साधनों के क्षेत्र में प्रगति) ।
10. Self Sufficiency (आत्मनिर्भरता) ।
11. Increase in health facility and Life expectancy (स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि) ।
12. Environment protection (पर्यावरण सुरक्षा) ।

• <u>असफलताएं (Failures):-</u>

1. Increase in unemployment (बेरोजगारी में भर्ती)।
2. Increase in economic disparities (आर्थिक विषमता में वृद्धि)।
3. Slow progress in per capita income and national income (प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में धीमी गति)।
4. Failure in industrial sector (औद्योगिक क्षेत्र में विषमता)।
5. Failure in the resources mobilization (साधन संग्रह के क्षेत्र में विषमताएं)।
6. Dependency on foreign Aid (विदेशी सहायता पर निर्भरता)।
7. Defective regulatory policy (दोषपूर्ण नियंत्रण रीति)।
8. Economic instability (आर्थिक अस्थिरता)।
9. Regional disparity regional disparity (क्षेत्रीय असंतुलन)।
10. Fail to control population (जनसंख्या नियंत्रण में विफल)।

Current Five Year Plan Objective Allocation And Targets
(विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में व्यूह रचना)

1. पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56):-

इस योजना का समय 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी । इस योजना में कृषि पर सर्वाधिक जोर दिया गया । इसके लिए सिंचाई तथा ऊर्जा परियोजना पर विशेष बल दिया गया । इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, और उसकी प्राप्ति 3.6% हुई।

2. दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61):-

इस योजना में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया था । प्राथमिक व भारी उद्योगों के विकास पर जोड़ दिया गया जोर दिया गया । इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया, और उसकी प्राप्ति 4.2% हुई।

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66):-

इस योजना में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था । विकास दर का लक्ष्य 5.6 प्रतिशत रखा गया , परंतु केवल 2.8% की प्राप्ति हुई। इसके कुछ मुख्य कारण थे 1962 में भारत-चीन युद्ध, 1965 में भारत-पाक युद्ध, लगातार दो वर्षों तक भयंकर सूखे, मुद्रा के अवमूल्यन, मूल्य वृद्धि आदि कारण थे।
इस दौरान 1966 से 1963 की अवधि के लिए चौथी योजना के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रारूप के अनुसार तीन वार्षिक योजना चलाई गई । तीन वर्षीय अवधि को योजनावकाश की संज्ञा दी गई । यह नियमित पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा नहीं है। इसे "अंतरिम प्लानिंग" भी कहा जाता है।

4. चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74):-

इस योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया , कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया । इसमें जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तथा शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर खास जोर दिया गया था । इस योजना काल में विकास दर का लक्ष्य 5.7% रखा गया, परंतु प्राप्ति 3.4% की हुई थी , कारण 1971 में भारत-पाक युद्ध और इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से आए लाखों शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

5. पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79):-

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना था । इसके साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया था । इसमें विकास दर 4.4% लक्ष्य रखा गया , और प्राप्ति 4.5% की मिली । 1977 में पहली बार गैर -कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पंचवर्षीय योजना की अवधि के 1 वर्ष कम कर दिया। यह केवल 4 वर्ष पूरा कर सका।

6. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85):-

इस योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया था । कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए उपाय सुझाए गए थे । विकास दर का लक्ष्य 5.2% था, जिसे 5.5% की दर से प्राप्त किया गया था।

7. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90):-

इस योजना में रोजगार , शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया । विकास दर का लक्ष्य 5% रखा गया और प्राप्ति 6% दर से हुई थी।

8. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97):-

इस योजना का मुख्य लक्ष्य 1990-91 में आई मुद्रास्फीति और बिगड़े भुगतान संतुलन को पटरी पर लाना था। विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया, और उसकी प्राप्ति 6.7% हुई।

9. नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002):-

स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे करने पर यह योजना लागू की गई थी । इसका मुख्य उद्देश्य मानव विकास के साथ-साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था । विकास दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया और प्राप्ति 5.5% की हुई थी।

10. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07):-

इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति था । 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना व 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षक पूरा करना था। सभी गांव को पीने का स्वच्छ पानी , प्रदूषित बड़ी नदियों की सफाई , वन व पेड़ों को लगाना , बुनियादी और सामाजिक क्षेत्रों में अधिक सरकारी निवेश संचालन कार्य को बेहतर बनाना था। विकास दर लक्ष्य 8% निर्धारित की गई परंतु 7.7% की प्राप्ति हुई।

11. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12):-

इस योजना में तीव्र एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया था । कृषि विकास के लिए नई तकनीकों के विकास हेतु शोध पर बल दिया गया । सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया गया। विकास दर लक्ष्य 9% रखा गया, और प्राप्ति 7.9% की हुई।

12. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17):-

इस योजना को आखरी पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है , क्योंकि 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है , बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य संसाधनों का विकास और ढांचागत परियोजनाओं के ऊपर ध्यान देना था। इसमें विकास दर 10% रखा गया, परंतु यह अल्पकाल में 5.5% दर प्राप्त कर सके।

New Economic Reforms- (LPG)

Liberalization	Privatization	Globalization
(उदारीकरण)	(निजीकरण)	(विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण)

नई आर्थिक नीति 1991(New Economic Policy 1991)

❖ अर्थ:-

नई आर्थिक नीति से अभिप्राय जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न आर्थिक उपायों व परिवर्तनों से है , जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी वातावरण तैयार कर उत्पादकता व कुशलता में वृद्धि करना है । सरकार ने जुलाई

1991 के बाद से देश को आर्थिक संकट से निकालने तथा विकास की गति को तीव्र करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाएं हैं–

1. नियंत्रित व्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति।
2. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
3. उत्पादन की उन्नत तकनीकी को अपनाना।
4. कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन।
5. राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण।
6. व्यापार, मौद्रिक व राजस्व नीति में व्यापक परिवर्तन।
7. सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।

❖ नई आर्थिक नीति के उद्देश्य(Objectives Of New Economic Policy)

1. अर्थव्यवस्था में विकास की दर को बढ़ाना।
2. उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना।
3. उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।
4. आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना।
5. पिछले वर्षों में प्राप्त लाभों का समायोजन करना।

- नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वव्यापीकरण करना है।

➢ उदारीकरण (Liberalization):-

Meaning:-

उदारीकरण के अंतर्गत सरकार आर्थिक क्रियाओं पर लगे हुए अनेक प्रतिबंधों को या तो पूर्ण रूप से हटा लेती है या फिर कुछ सीमा तक मुक्त कर देती है । उदारीकरण से आशय है , सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं में छूट देना । इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है-

i. वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लगी रुकावटों व नियंत्रणों को हटाना।
ii. निजी उपक्रम एवं पूंजी को बढ़ती मात्रा मे निवेश के अवसर प्रदान करना।
iii. निजी उपक्रम एवं पूंजी पर लगी रुकावटों को हटाना।
iv. वस्तुओं की कीमतों पर निर्धारण उत्पादकों द्वारा किया जाना।

- **उदारीकरण नीति के उद्देश्य(Objectives Of Liberalization Policy)**

i. घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार तथा उत्पादन क्षमता में विकास करना।
ii. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
iii. वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
iv. अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होना।

➢ निजीकरण (Privatization):-

Meaning: -

निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों के स्वामित्व को सरकार से निजी उद्यमियों को किए जाने वाले हस्तांतरण से है। निजीकरण में आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकारी नियंत्रण को कम करके देश में आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित किया जाता है।

- **<u>विशेषताएं (Features):-</u>**

i. निजीकरण एक नई अवधारणा है।
ii. निजीकरण आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने का एक साधन है।
iii. निजीकरण की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप में अपनाई जाती है।
iv. निजीकरण में सरकारी प्रभुत्व कम किया जाता है।
v. निजीकरण सार्वजनिक स्वामित्व को निजी स्वामित्व में परिवर्तित कर देता है।

- **<u>उद्देश्य (Objectives):-</u>**

i. औद्योगिक शांति की स्थापना करना।
ii. उद्योगों की निष्पादन क्षमता में सुधार करना।
iii. देश में उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना।
iv. देश में तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का वातावरण तैयार करना।
v. देश में उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना।
vi. उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का विकास करना।
vii. सार्वजनिक उद्योगों के घाटे के भार से सरकार को मुक्ति दिलाना।

➢ <u>उदारीकरण एवं निजीकरण में अंतर</u>

- उदारीकरण एक व्यापक धारणा है , जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में लागू की जा सकती है , और निजीकरण एक संकुचित धारणा है और उसे विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आसानी से अपनाया नहीं जा सकता। निजीकरण उदारीकरण का एक अंग है।
- उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण होता है, और निजीकरण में स्वामित्व एवं नियंत्रण व्यक्ति को होता है।
- उदारीकरण में सार्वजनिक लाभ की भावना होती है, जबकि निजीकरण में निजी लाभ की भावना होती है।

➢ <u>वैश्वीकरण विश्वव्यापीकरण (Globalization):-</u>

<u>Meaning:-</u>

प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु , सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान -प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के लिए सभी प्रकार की रुकावटें हटा ली जाती है। इस प्रकार वैश्वीकरण शब्द से तात्पर्य विश्व एक बाजार के रूप में से होता है।

- **<u>विशेषताएं:-</u>**

i. देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है।
ii. बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है।
iii. वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है।
iv. विश्व एक बाजार के रूप में होता है।

- **<u>उद्देश्य:-</u>**

i. ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का स्वतंत्र प्रवाह हो सके।
ii. ऐसा वातावरण कायम करना, कि टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके।

iii. ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके।
iv. व्यापार-अवरोधों को (Trade Barriers) को कम करना, ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोकटोक आदान-प्रदान हो सके।

आर्थिक सुधार के पीछे तर्क (Relation Behind Economic Reforms)

भारत में आर्थिक सुधार करने के पीछे निम्नलिखित तर्क या कारण हैं-

i. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ-साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था।
ii. मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना।
iii. आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना।
iv. आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना उसके साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना था।
v. प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना था।
vi. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था।
vii. 1991 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी।
viii. राजकोषीय घाटा से उबरने के लिए सुधार किए गए थे।
ix. संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से तथा भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आर्थिक सुधार को अपनाया गया।

वैश्वीकरण और निजी करण की प्रगति (Progress Of Privatization And Globalization):-

निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने से निम्नलिखित प्रगति/उपलब्धियां मिली:-

1. राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर (National Income Growth Rate):-

1990 से 91 में वास्तविक राष्ट्रीय आय 5.4% थी, लेकिन नयी आर्थिक नीति लागू होने के बाद 1996-97 में यह बढ़कर 8.2% हो गयी तथा 2000-2001 में घटकर 3.7% हो गई।

2. कृषि उत्पादन (Agriculture Production):-

1990-91 में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर 3% थी तथा खाद्यान की वृद्धि दर 3.2% थी। 1996-97 में कृषि विकास दर बढ़कर 9.6% हो गयी, लेकिन इसके बाद 1997-98, 1999-2000 तथा 2000-2001 में ऋणात्मक रही। 2001-2002 में विकास दर 9.7% अनुमानित की गई।

3. औद्योगिक उत्पादन (Industrial Production):-

भारत में नये आर्थिक सुधार अपनाए जाने का उद्देश्य उदारवादी नीति , उद्योगों का निजीकरण व वैश्वीकरण के द्वारा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है , आठवीं योजनाकाल में वृद्धि दर 7.5% निर्धारित की गई थी । विभिन्न वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में उतार चढाव होते रहे हैं।

4. कीमत स्तर (Price Level):-

1991 के बाद कीमत स्तर में काफी हद तक कम करने में सफल रहा । 1990-91 में कीमत स्तर की वार्षिक वृद्धि दर 12% थी, जो 1995-96 में 4.4%, 1999-2000 में 6.5%, 2000-2001 में 4.9% रही है। 2007 में 6.1% मुद्रा स्फीति थी।

5. विदेशी विनिमय मुद्रा कोष (Foreign Currency Reserves):-

नई आर्थिक नीति का विदेशी विनिमय मुद्रा कोष पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है । 1990-91 में विदेशी विनिमय मुद्रा कोष 4,388 करोड रुपए थी , जो कि बढ़कर 1999 -2000 में 1 ,52,924 करोड रुपए तथा 200 1-2002 में 46 ,561 करोड रुपए हो गयी ।

6. निर्यात (Export):-

नए आर्थिक सुधार लागू होने के बाद देश का निर्यात काफी बढ़ा है । 1990-1991 में निर्यात वृद्धि दर 17.7% थी , जो 1991-92 में 35.5% हो गई, 2005-2006 में 23.4% थी ।

7. आयात (Import):-

आयात में काफी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही , आर्थिक सुधार के प्रारंभिक वर्ष में पहले 1990 -91 में आयात में वृद्धि दर 22.3% थी, जो 1991-92 में 10.8%,1992-93 में काफी वृद्धि हुई । 2005-2006 में आयात वृद्धि 33.8% रही ।

8. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment):-

आर्थिक सुधार के उदारवादी दृष्टिकोण के कारण भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में काफी वृद्धि हुई । FDI 1990-91 में 97 Million US Dollar था, जो 2000-2001 में 2,339, 2001-2002 में 2,365 Million US Dollar था, 2005-2006 में शुद्ध FDI 4,720 Million US Dollar था ।

9. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):-

भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य राजकोषीय घाटा कम करना था । 1990-91 में जीडीपी का 6.6% , जो घटकर 1999-2000 में 5.4%, 2000-2001 में 5.5% हो गया । 2001-2002 में 5.1% तथा 2007-2008 में 3.3% था ।